में है।

(ख) इस परियोजना के लाभ और लागत को दोनों राज्यों के बीच बराबर बांटने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश ने 133 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है जबकि मध्य प्रदेश ने 87 करोड़ रुपये का अंशदान किया है।

(ग) राजघाट बांध परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 46 करोड़ रुपये की वित्तीय देयता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 के दौरान 23 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की है जिसमें से 11.5 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

गंगऊ पर भंडारण बांध

2621. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे **:**

(क) क्या केन नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक संयुक्त नदी है, और मध्य प्रदेश द्वारा इस नदी के साथ गंगऊ स्थान पर एक भंडारण बांध का निर्माण करने की एक संयुक्त परियोजना प्रस्तावित है और क्या अनुमानित जल की उपलब्धता और उसके वितरण के संबंध में दोनों राज्यों के बीच सहमति न हो पाने के कारण इस परियोजना को अंतिम रूप नही दिया जा सका;

(ख) क्या केन बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बांध में भंडारित जल बांदा जिले के क्षेत्रों के लिए सिंचाई साधन के रूप में लाभकारी होगा; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) गंगऊ परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के बाद इस परियोजना की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है।

Pending Water Disputes

2622. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 448 given in the ajya Sabha on 25th February, 1999 and state:

(a) whether Government have adopted any new strategy to settle the pending disputes among States on the Inter-State Water disputes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOM PAL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Reliability and efficiency of cyclone forecasting

2623. SHRI LAJPAT RAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the machinery for flood and cyclone forecasting is working efficiently and reliably;

(b) if so, the track record of flood and cyclone forecasting in our country; and

(c) the steps taken/being taken to improve the efficiency and reliability in flood forecasting?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The record of flood forecasting activities of Central Water Commission and that of cyclone forecasting of India Meteorological Department have been satisfactory and have been appreciated for the reliability and timely forecasts, particularly of major flood and cyclone events. The performance in terms of accuracy of flood forecasts ranges between 94% to 98% in the last ten years. India's cyclone forecasting capability is such that no cyclone approaching Indian Coast from any part of the Indian Ocean can escape detection.

(c) To improve the efficiency and reliability of flood forecasts, the techniques are being constantly reviewed, updated and modernised. The communication system is constantly modernised by introducing satellite technology to advance the warning time and quicken the data transmission.

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रुपेन नदी और बाण सागर परियोजना संबंधी समझौता

2624. **श्री चुन्नी लाल चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**